

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2018



**प्रयोग समाज सेवी संस्था  
तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़**

## पृष्ठभूमि -

प्रयोग समाज सेवी संस्था की स्थापना वर्ष 1975 से आरंभ हुआ और पंजीयन वर्ष 1982 में हुआ। प्रयोग की पहचान एक ऐसे संस्था के रूप में रही है जिसने ग्रामीण नेतृत्व को विकसित किया है। प्रयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवक युवतियों के लिए 'गांधीयन एक्टिविज्म स्कूल' के रूप में केन्द्र को विकसित किया है। अभी तक 2000 से भी ज्यादा युवाओं को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जो राज्यभर में कार्यरत हैं।

संस्था द्वारा दलित, आदिवासी एवं भूमिहीनों के लिये किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है -

- आदिवासी और भूमिहीनों को संगठित और एकजुट करना तथा स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाना।
- शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन की दिशा में जागरूक करना ताकि अधिकाधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन व अपने अधिकारों के प्रति सामूहिक प्रयास करना।
- संघर्ष, रचना व संवाद के माध्यम से अधिकारों के लिए जागरूक करना।
- समुदाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा जल, जंगल, जमीन व आजीविका के अधिकार के लिए सामूहिक पहल करना।
- जागरूकता निर्माण और मोबिलाईजेशन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक केन्द्रित विकास के लिए जवाबदेह संसाधन प्रबंधन, भूमि वितरण, आदिवासी समाज की जंगल में पहुंच (उपयोग-उपभोग), विकेन्द्रिकृत निर्णयों और सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

## संस्थागत कार्यक्षेत्र

संस्था द्वारा वर्ष 2018 में चार राज्यों में व्यापक तौर पर संगठन निर्माण, युवा एवं महिला नेतृत्व निर्माण, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अधिकाधिक हितग्राहियों को खाद्यान्न आपूर्ति व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कार्यक्षेत्र में संचालित समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन" तथा "आवासीय भूमि अधिकार कानून" को लागू करने जैसे नीतिगत बदलाव की दिशा में प्रयास कर रही है।

**राज्यवार कार्यक्षेत्र का विवरण -**

क्र.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लॉक संख्या	पंचायत संख्या	गांव संख्या		
					सघन	सम्पर्क	कुल
1	छत्तीसगढ़	18	23	393	439	292	731
2	मध्यप्रदेश	18	43	472	472	314	786
3	उड़ीसा	09	14	75	225	150	375
4	झारखण्ड	06	16	58	145	97	242
		<b>51</b>	<b>96</b>	<b>998</b>	<b>1281</b>	<b>853</b>	<b>2134</b>

**संस्था द्वारा संचालित परियोजनाएँ -**

1. डब्ल्यू.एच.एच., नई दिल्ली के सहयोग से संगठन निर्माण परियोजना ।
2. आई.जी.एस.एस.एस., नई दिल्ली के सहयोग से “आजीविका के उत्थान का स्थायी विकल्प” परियोजना ।
3. यूनिसेफ रायपुर के सहयोग से “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” पर अभियान ।
4. “फाओ” इटली के सहयोग से कानूनी सलाह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम ।

जनवरी से दिसम्बर 2018 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से की गई विभिन्न गतिविधियाँ

**1. संगठन निर्माण परियोजना**

- **श्रमदान शिविर/ कौशल विकास प्रशिक्षण** - सामुदायिक श्रम को प्रोत्साहित करने तथा सामुदायिक पहल द्वारा गांव स्तर पर स्थायी ढाँचा तैयार करने की दृष्टि से परियोजना क्षेत्र के चार राज्यों में 19 श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तालाब गहरीकरण, चेक डेम निर्माण तथा कच्चा सड़क बनाने का कार्य किया गया । जो छत्तीसगढ़ में 7, मध्यप्रदेश में 8, उड़ीसा में 3 तथा झारखण्ड में 2 शिविर का आयोजन किया



गया, जिसमें 1976 युवक/युवती तथा ग्रामीण मुखियाओं ने भाग लिया । इस श्रमदान शिविर में लगभग 39,80,000 रु. का सामूहिक श्रम किया गया । इन शिविरों से प्रेरित होकर अन्य गांवों में भी 48 श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भी 37,69,186 रु. का सामूहिक श्रमदान कर गांव के विकास में रचनात्मक कार्य किये गये ।



- **नेतृत्व विकास प्रशिक्षण** - जन आंदोलन 2018 को सफल बनाने का लिए नेतृत्वकर्ताओं का समूह बनाया गया था, जिसमें 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति तथा 500 व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 4 राज्यों के 1560 नेतृत्वकर्ताओं का प्रशिक्षण विभिन्न समयावधि में किया गया । यह आयोजन पूरी तरह जनाधारित कार्यक्रम था ।
- **ब्लॉक/ तहसील/ जिला/ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेसी** - जन आंदोलन जैसे व्यापक कार्यक्रम में सहभागी होने के पूर्व परियोजना क्षेत्र के 4 राज्यों के प्रत्येक जिले/ तहसील स्तर पर लम्बित दावों के संबंध में अवगत कराना तथा निराकरण करने की दिशा में पहल करना था। साथ ही जनांदोलन 2018 के मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया गया था, जिसे परियोजना क्षेत्र के सभी जिलों के तहसील स्तर पर संवाद कार्य किया गया ।
- **हस्ताक्षर अभियान** - जन आंदोलन 2018 की प्रमुख 6 मांगों को लेकर परियोजना क्षेत्र के 4 राज्यों के 50 जिलों में सामुदायिक सदस्यों/ अन्य हितधारकों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भेजे जाने वाले मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें परियोजना क्षेत्र के 1,02,000 व्यक्तियों का हस्ताक्षर कराया गया, जिसे राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया ।



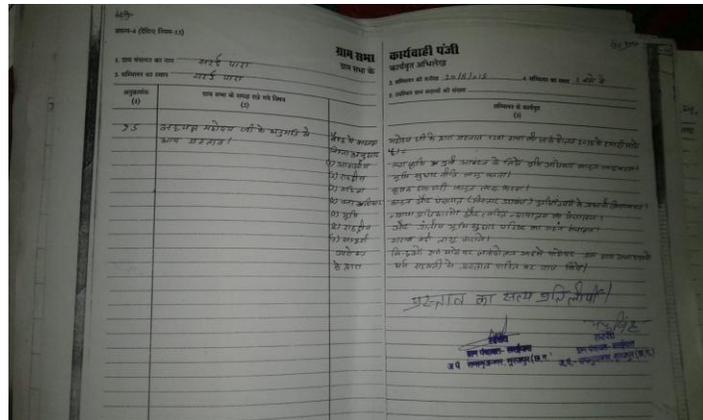
- **अन्नदान अभियान** - 2 अक्टूबर 2018 से होने वाले राष्ट्र-व्यापी आंदोलन के लिए परियोजना क्षेत्र से 20000 सत्याग्रहियों की शामिल होने की योजना थी, जिसके भोजन व अन्य व्यवस्था हेतु अन्नदान अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1850 किंचटल अनाज तथा 4,10,000 नगद राशि का संकलन किया गया ।



- **ग्रामकोष व अनाज कोष** - इस परियोजना के तहत 2170 गांव है, जिसमें से 1500 गांवों में सघन रूप से संगठन सशक्तिकरण के लिए ग्रामकोष व अनाज कोष संकलन किया जाता है, जिसके तहत 37,50,000 को ग्रामकोष व 2675 किंचटल अनाज का संकलन किया गया है ।

- **हस्ताक्षर अभियान** - इस परियोजना में सदस्यता निर्माण मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 30 प्रतिशत सदस्यों का निर्माण करना निहित था । वर्ष 2018 के दौरान 6850 सदस्य बनाये गये ।

- **100 गांवों का माइक्रोप्लानिंग** - परियोजना क्षेत्र के 50 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम 2 गांवों में सामुदायिक विकास के कार्य के लिए माइक्रोप्लान तैयार कर ग्रामसभा में अनुमोदित कराना था, जिसके तहत वर्ष 2018 के दौरान जनांदोलन के 6 मांगों के लिए 145 प्रस्ताव तथा अन्य विकासकारी योजनाओं के लिए 65 प्रस्ताव ग्रामसभा में अनुमोदित किया गया ।



- **25 मॉडल गांव का निर्माण** - परियोजना क्षेत्र के 50 जिलों में से कम से कम 25 गांवों में मॉडल गांव तैयार करना था, जिसमें वर्ष 2018 के दौरान 58 गांवों को समुदाय आधारित मॉडल गांव बनाया गया, जिसमें सामुदायिक सहभागिता, संघर्ष तथा संवाद करने की क्षमता विकसित किया गया है । इन 58 गांवों में समुदाय आधारित रचनात्मक कार्य का बेहतर नमूना भी खड़ा किया गया है ।

- **25 सहयोगी संगठन के साथ जुड़ाव** - इस परियोजना के माध्यम से छोटे-छोटे अन्य समान विचारधारा के सहयोगी संगठनों का संस्थागत तथा वित्तीय



- शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों या पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का जिला स्तरीय शिक्षा प्रोत्साहन समूह का स्थापना ।

- चूंकि यह परियोजना अक्टूबर 2018 से क्रियाशील हुआ है, अतः अभी तक निम्नलिखित गतिविधियाँ ही संचालित हो सकी है -

- “सीख” अभियान के सभी स्टॉफ का उन्मुखीकरण कार्यशाला 29 से 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया, जिसमें 18 फेसिलिटेटर, मैनेजर्स तथा जिला सीख समन्वयक शामिल हुए ।



- नये संदर्भ में शालाओं का चयन तथा समुदाय सम्पर्क किया गया ।
- शिक्षा को पंचायत स्तर के कार्यक्रम में प्रमुखता से शामिल करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।
- सीख प्रोत्साहन केन्द्र के लिए सरपंच व सचिव के साथ संवाद करना तथा सीख प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना करना ।
- “सीख” कार्यक्रम के तहत 9 संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसके साथ इस अभियान का संचालन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है -
  - प्रयोग समाज सेवी संस्था
  - निर्माण सेवा समिति
  - कल्याणी सोशल वेल्फेयर एंड रिसर्च आर्गनाइजेशन
  - समता जन कल्याण समिति
  - जन सहयोग सेवा समिति
  - लोक आस्था सेवा संस्थान
  - सहभागी समाज सेवी संस्था
  - साथी समाज सेवी संस्था
  - जन कल्याण सामाजिक संस्थान

### 3. जैविक खेती के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा :

संस्था द्वारा जिला कबीरधाम, सरगुजा और जशपुर के 30 गांवों में संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा और बैगा समुदाय के मध्य जैविक खेती के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा की दिशा में के बीच में किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के माध्यम से निम्न-लिखित गतिविधियों संचालित की जा रही है -

- प्रत्येक परिवार में कम्पोस्ट बॉक्स व किचन गार्डन तैयार करना ।
- बहु फसलीय तथा मिश्रित खेती को प्रोत्साहन देना ।
- उद्यानिकी तथा फूलों की खेती प्रारंभ करना व जैविक खेती के लिए प्रत्येक परिवार को जागरूक करना ।
- पशुपालन के लिए प्रेरित करना ।
- शासकीय योजनाओं - विधवा-वृद्धावस्था तथा विकलांग को पेंशन, मनरेगा के तहत काम की मांग व समय पर मजदूरी भुगतान, गरीबी रेखा कार्ड, वनाधिकार के तहत अधिकार पत्र, अन्त्योदय जैसे अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना ।
- एस.एच.जी. के माध्यम से अन्य वित्तीय संस्थाओं से फण्ड लेना तथा अनेक आर्थिक कार्यक्रमों के संचालन से जीवन स्तर में बदलाव लाना ।

उपरोक्त गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक परिवार में 9 से 12 माह का खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसके तहत 700 परिवारों में से 425 परिवारों का 9 से 12 माह तक भोजन आपूर्ति हो सका है ।

(अरुण कुमार)  
सचिव

## संस्थागत कार्यक्षेत्र

क्र.	राज्य	जिला का नाम		ब्लॉक संख्या	पंचायत संख्या	गांव संख्या
1	छत्तीसगढ़	1	राजनांदगांव	1	15	40
		2	नारायणपुर	1	18	40
		3	कोण्डागांव	1	43	43
		4	कांकेर	1	13	45
		5	धमतरी	2	11	43
		6	गरियाबंद	1	17	43
		7	महासमुन्द	1	22	40
		8	रायपुर	1	37	43
		9	बलौदाबाजार	1	31	31
		10	बिलासपुर	1	26	39
		11	मुंगेली	1	11	40
		12	सरगुजा	2	20	64
		13	कोरिया	1	16	41
		14	बलरामपुर	2	11	40
		15	सूरजपुर	2	36	41
		16	जशपुर	2	36	48
		17	रायगढ़	1	28	40
		18	कबीरधाम	1	2	10
				<b>23</b>	<b>393</b>	<b>731</b>
2	मध्यप्रदेश	1	मुरैना	4	24	55
		2	श्योपुरकलौ	1	25	40
		3	ग्वालियर	3	36	40
		4	शिवपुरी	2	33	50
		5	विदिशा	2	37	40
		6	सागर	3	38	45
		7	टीकमगढ़	4	36	46
		8	दमोह	2	19	40
		9	सीधी	4	27	40
		10	शहडोल	3	27	46
		11	उमरिया	3	21	40
		12	जबलपुर	3	33	40
		13	सिवनी	1	25	40
		14	बालाघाट	2	14	41
		15	रायसेन	2	26	50

		1 6	सिहोर	2	25	51
		1 7	झाबुआ	1	18	42
		1 8	अलीराजपुर	1	8	40
				<b>43</b>	<b>472</b>	<b>786</b>
3	उड़ीसा	1	कालाहण्डी	1	3	40
		2	कंधमाल	1	5	40
		3	सुन्दरगढ़	2	12	40
		4	रायगड़ा	3	11	44
		5	बालोंगीर	1	10	40
		6	नयागढ़	1	3	46
		7	जाजपुर	1	10	40
		8	पुरी	3	11	45
		9	खुर्दा	1	10	40
				<b>14</b>	<b>75</b>	<b>375</b>
4	झारखण्ड	1	पलामू	3	9	40
		2	गुमला	3	9	40
		3	चतरा	3	10	40
		4	हजारीबाग	2	9	40
		5	धनबाद	2	14	42
		6	कोडरमा	3	7	40
				<b>16</b>	<b>58</b>	<b>242</b>
	कुल		<b>51</b>	<b>96</b>	<b>998</b>	<b>2134</b>